न्यूनतम समर्थन मूल्य

वर्तमान संदर्भ

भारत की प्रमुख तिलहनी फसलों में से प्रमुख फसल 'सरसों' के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे आ गए है।

Follow Us: @khanglobalstudies

विवरण

01

बेमौसम बारिश के कारण सरसों में उच्च नमी **और पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे अन्य खाद्य तेलों के अपेक्षाकृत सस्ते आयात** ने सरसों की कीमतों को MSP स्तर से नीचे ला दिया है।

02

सरसों के शीर्ष उत्पादक राज्य राजस्थान में, 5,450 रुपये प्रति क्विंटल MSP की तुलना में सरसों की कीमतें वर्तमान में 5,100-5,200 रुपये प्रति क्विंटल के लगभग चल रही हैं। जबकि पिछले साल इसी समय यह करीब 6,500 रुपये प्रति क्विंटल था।

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है?

01

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत गठित आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा निर्धारित वह न्यूनतम कीमत है, जो किसानो के कृषि उत्पाद को उचित कीमत देने की गारंटी देती है।

02

इसका प्रमुख **उद्देश्य किसानों को संकटकालीन बिक्री के समय सहायता देना और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों की खरीद करना है।**

03

न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा **कृषि लागत और मूल्य आयोग** (Commission for Agricultural Costs and Prices-CACP) की सिफारिशों के आधार पर कुछ फसलों के लिए **बुवाई के मौसम की शुरुआत में** की जाती है।

04

खरीफ फसलों के लिए MSP में वृद्धि **केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा** के अनुरूप है **जिसमें MSP को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत (CoP) के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की घोषणा की गई है,** जिसका लक्ष्य किसानों के लिए यथोचित उचित पारिश्रमिक देना है।

05

सरकार **22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य** (Fair And Remunerative Price—FRP) **की घोषणा करती है।** अनिवार्य फसलों में **खरीफ की 14 फसलें, रबी की 6 फसलें और दो अन्य व्यावसायिक फसलें हैं।** इसके अलावा तोरिया और छिलके वाले नारियल (de-husked coconut) का MSP क्रमशः रेपसीड/सरसों और कोपरा **के MSP के आधार पर तय किया जाता है।**

MSP का निर्धारण निम्नलिखित कारकों पर आधारित है

- उत्पादन लागत
- आगत कीमतों में बदलाव
- आगत-निर्गत मूल्य समानता
- बाजार मूल्यों में रुझान
- मांग और आपूर्ति
- अंतर-फसल मूल्य समानता
- औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव
- जीवन यापन की लागत पर प्रभाव
- सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव
- अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति
- भुगतान की गई कीमतों और किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों के बीच समानता
- निर्गम कीमतों पर प्रभाव और सब्सिडी हेतु निहितार्थ

राष्ट्रीय किसान आयोग : स्वामीनाथन समिति

- वर्ष 2004 में केंद्र सरकार ने एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग (NCF) का गठन किया, जिसमें कृषि वस्तुओं को लागत-प्रतिस्पर्धी और अधिक लाभदायक बनाने के लिए एक स्थायी कृषि प्रणाली तैयार करने को कहा गया। वर्ष 2006 में इस समिति ने सुझाव दिया कि MSP उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए।
- इस समिति ने तीन स्तरों पर खेती की लागत के बारे में चर्चा की :

01 **ए2 :** इसमें फसल पैदा करने के लिए सभी प्रकार के **नकद व्यय** जैसे बीज, खाद, रसायन, श्रम लागत, ईंधन लागत और सिंचाई लागत **शामिल** हैं।

02 **ए2+एफएल** : इसमें अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक आरोपित मूल्य ए2 प्लस शामिल है।

03 **सी2 :** सी2 के तहत जमीन का अनुमानित किराया और खेती हेतु लिए गए पैसे पर ब्याज की लागत को ए2 और एफएल में जोड़ा जाता है।

चुनौतियां

01 अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित दरों से अधिक MSP भारत के कृषि निर्यात को प्रभावित करेगा। भारत के निर्यात का 11 प्रतिशत हिस्सा कृषि उत्पाद का हैं।

02 भारतीय खाद्य निगम द्वारा पीडीएस के तहत ली जाने वाली चावल और धान को छोड़कर सभी फसलों को खरीदने के लिए सरकारी मशीनरी की कमी एक और बड़ी चुनौती है।

03 MSP आधारित खरीद प्रणाली बिचौलियों, कमीशन एजेंटों और एपीएमसी प्रतिनिधियों पर भी निर्भर करती है, उन तक छोटे किसानों का पहुंचना मुश्किल होता है।

आगे की राह

हाल ही में सरकार ने MSP प्रणाली की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के लिए भी फायदेमंद होगा। यह कृषि बाजार के पुनर्गठन और किसान की आय को दोगुना करने में मदद करेगा।

Minimum Support Price

Current Context

Prices of mustard seeds, one of the main oilseed crops of India, crashed below the minimum support price (MSP).

Follow Us: @khanglobalstudies

About

01

High moisture in mustard due to **unseasonal rainfall and cheaper import** of other cooking oils like palm, soybean and sunflower have dragged the mustard prices below the **MSP** level.

As against the MSP of Rs 5,450/quintal, mustard prices are currently ruling around Rs 5,100-5,200/quintal in Rajasthan, the top producer of the crop. Last year around this time, it was around Rs 6,500/quintal.

02

What is Minimum Support Price?

01 Minimum Support Price (MSP) is **a form of market intervention** by the Union Ministry of Agriculture, to insure agricultural producers against any sharp fall in farm prices.

02 The major objectives are **to support the farmers from distress sales and to procure foodgrains for public distribution.**

03 The minimum support prices are announced by the Government of India **at the beginning of the sowing season** for certain crops on the basis of the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP).

04 The increase in MSP for the Kharif Crops is in line with the **Union Budget 2018-19** announcement of fixing the MSPs at a level **of at least 1.5 times of the All-India weighted average Cost of Production (CoP),** aiming at reasonably fair remuneration for the farmers.

05 The Government announces MSP **for 22 mandated crops and fair and remunerative price (FRP) for sugarcane.** The mandated crops are **14 crops of the kharif season, 6 rabi crops and two other commercial crops.** In addition, the MSPs of toria and de-husked coconut are fixed on the basis of the **MSPs of rapeseed/mustard and copra,** respectively.

Determination of MSP is based on the following factors

- Cost of production
- Changes in input prices
- Input-output price parity
- Trends in market prices
- Demand and supply
- Inter-crop price parity
- Effect on industrial cost structure
- Effect on the cost of living
- Effect on the general price level
- International price situation
- Parity between prices paid and prices received by the farmers.
- Effect on issue prices and implications for subsidy.

National Commission on Farmers: Swaminathan Committee

- In 2004, the Union government formed the National Commission on Farmers (NCF) with MS Swaminathan as its chairman, to come up with a sustainable farming system, make farm commodities cost-competitive and more profitable. **In 2006, the Committee recommended that MSPs must be at least 50% more than the cost of production.**
- **It talked about the cost of farming at three levels:**

01 **A2:** It includes all types of cash expenditure to generate the crop like seeds, manure, chemicals, labour costs, fuel costs and irrigation costs.

02 A2+FL: It includes A2 plus an imputed value of unpaid family labour.

03 **C2:** Under C2, the estimated land rent and the cost of interest on the money taken for farming are added to A2 and FL.

Challenges

01 The MSP higher than the prevailing rates in the international market will affect India's agri exports. 11% of all exports are agricultural products.

02 Lack of government machinery to buy all crops except rice and paddy, which are taken under PDS by the Food Corporation of India, is another major challenge.

03 The MSP-based procurement system also relies on intermediaries, commission agents, and APMC representatives, all of whom smaller farmers find difficult to reach.

Way Forward

Recently, the government has set up an expert committee to review the MSP system which will be beneficial for farmers as well as for consumers. It will help in restructuring agriculture market and doubling farmers' income.